

सवालों का घेरा

प्रवेश परीक्षाओं की प्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने का मुद्दा अब सड़क से लेकर संसद तक पहुंच गया है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष इस मसले को जोर-शोर से उठा रहा है। संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यह सच है कि देश का संविधान हर नागरिक को इजाजत देता है कि वह शासन-प्रशासन या किसी संस्था की नीतियों और निर्णयों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना असंतोष और मांग जाहिर कर सकता है। ऐसे में क्या वजह रही कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं से संवाद के बजाय उनके खिलाफ बल प्रयोग करने को ही अंतिम विकल्प मान लिया गया! क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि प्रदर्शनकारी युवाओं की मांग पर विचार किया जाए और समाधान का कोई रास्ता निकाला जाए? यही नहीं, संसद में इस मुद्दे पर बने गतिरोध से जो कीमती समय बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? संसद का काम जनहित से जुड़े मसलों पर मंथन कर उन्हें निर्णायक रूप देने का होता है, मगर जब सदन में कोई कामकाज ही नहीं होगा, तो फिर उसके मूल उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो पाएगी।

दरअसल, नीट में गड़बड़ियों को लेकर काकरोच जनता पार्टी (काजपा) की ओर से जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मैत्र प्रधान के इस्तीफे और प्रवेश परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। इस मामले ने बीते शनिवार को तब तूल पकड़ा, जब बीस दिनों से अनशन पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसे युवाओं के आंदोलन की आवाज को दबाने के प्रयास के रूप में देखा गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान सुरक्षा बलों के बल प्रयोग से स्थिति बिगड़ गई और कई जगह दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। मगर अहम सवाल यह है कि यह नौबत आने ही क्यों दी गई? सरकार ने समय रहते प्रदर्शनकारी युवाओं से बातचीत कर उन्हे भरोसे में लेने की कोशिश क्यों नहीं की? जाहिर है, अगर सरकार की ओर से यह पहल की जाती, तो प्रदर्शनकारियों के संसद तक मार्च को टाला जा सकता था।

प्रदर्शनकारी युवा अब भी जंतर-मंतर पर डटे हुए हैं और वे अपनी मांगों पर अडिग हैं। वहां ज्यादा भीड़ जमा न हो, इसके लिए बुधवार को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सत्रह स्टेशनों को बंद कर दिया। मगर इसका खमियाजा उन सैकड़ों यात्रियों को भी भुगताना पड़ा, जो अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए मेट्रो से सफर करते हैं। कई लोगों को अपने गंतव्य से पहले ही मार्ग बदलना पड़ा या फिर कई किलोमीटर दूर से वापस सड़क मार्ग से गंतव्य स्थल तक पहुंचना पड़ा। सवाल यह भी है कि क्या युवाओं को विभिन्न तरकीबों के जरिए प्रदर्शन से दूर रखने से उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? दूसरी ओर, विपक्षी दल भी प्रदर्शनकारी युवाओं की मांगों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। विपक्ष की ओर से संसद में इस मुद्दे को उठाए जाने और हंगामे के कारण दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विपक्ष और सत्तापक्ष की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जंतर-मंतर पर डेरा डाले युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और संवाद के जरिए समाधान का रास्ता निकाला जाए।

सुरक्षा की खातिर

सिक्किम के नामची जिले में बीते सोमवार को भूस्खलन के कारण एक सुरंग के ढह जाने से कई लोगों की मौत हो जाने की घटना ने पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहाड़ों की पारिस्थितिकी की अनदेखी कर विकास कितना नुकसानदेह हो सकता है, यह अब कोई छिपी बात नहीं है। उत्तराखंड और तेलंगाना में भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनसे कोई सबक नहीं लिया गया। यह जानते हुए कि हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन एक बड़ी चुनौती है, इसके बावजूद अगर सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन न किया जाए, तो इसे लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा। सवाल है कि जब बरसात के मौसम में सुरंग का निर्माण कार्य किया जा रहा था, तो वहां आपात स्थिति के लिए पहले से सुरक्षा उपाय करने पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? इस हादसे में जिन श्रमिकों की जान चली गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए परियोजना का काम संभाले संबंधित उच्चाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी?

गौरतलब है कि नामची जिले में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन की तीस्ता-छह जल विद्युत परियोजना के लिए सुरंग बनाई जा रही है, जो भूस्खलन के कारण अचानक ढह गई। हादसे के वक्त वहां परियोजना अधिकारी सहित पच्चीस श्रमिक मौजूद थे, जिनमें से बीस की मौत हो जाने की पुष्टि की गई है। भू-वैज्ञानिकों के मुताबिक, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार निर्माण कार्यों और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण मिट्टी एवं चट्टानों की पकड़ ढीली पड़ रही है। ऐसे में बारिश के दिनों में हर समय भूस्खलन का जोखिम बना रहता है। पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और सिक्किम में कई सुरंगों का निर्माण किया गया है और कुछ का कार्य प्रगति पर है। सवाल है कि सुरंग बनाने से पहले पर्यावरण से जुड़े खतरों का पूर्व में स्टीक आकलन क्यों नहीं किया जाता? अगर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए, तो बड़ी दुर्घटनाएं टाली जा सकती हैं। समय आ गया है कि पर्यावरण के साथ संतुलन बना कर विकास कार्यों की योजनाएं बनाई जाएं, ताकि पहाड़ों के पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य दोनों की रक्षा की जा सके।

संकट के मुहाने पर अर्थव्यवस्था



प्रमोद कुमार बाजपेई

कुछ समय पहले भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर था, मगर अब वह पिछड़ कर छठे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं, जापान और ब्रिटेन ने अपनी स्थिति पुनः हासिल कर ली है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञ इसके लिए डालर के मुकाबले गिरते रुपए को प्रमुख कारण मान रहे हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,813 अमेरिकी डालर है, जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय 14,874 अमेरिकी डालर है, जो भारत की प्रति व्यक्ति आय की लगभग पांच गुना है। यह स्थिति तब है, जब भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर लगभग साढ़े छह फीसद बनी हुई है। चालू वर्ष के शुरुआती पांच महीनों में ही विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए, जो पिछले पूरे साल के 1.7 लाख करोड़ रुपए के रिकार्ड से कहीं अधिक है। शेरय बाजार की इस उथल-पुथल से हर कोई हैरान है।

एक समय था जब ‘म्यूचुअल फंड सही है’ पर जोर दिया जाता था, लेकिन अब एसोसिएशन आफ म्यूच्युल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों से एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। देसी और विदेशी निवेशकों का भरोसा इस कदर डगमगा रहा है कि बड़े पैमाने पर खाते बंद हो रहे हैं। ‘सिप बंद’ करने का अनुपात बढ़ कर मार्च और अप्रैल में सौ फीसद से ऊपर चला गया था, जिसका अर्थ है कि नई शुरु होने वाली सिप से ज्यादा पुरानी सिप बंद या ‘मैच्योर’ होने पर उससे पैसा निकाल लिया गया। उदाहरण के लिए, अप्रैल में 50.71 लाख नए सिप पंजीकृत हुए, जबकि 51.29 लाख खाते बंद हुए। मई में भी यह अनुपात 95 फीसद के करीब रहा। विदेशी संस्थागत निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा कमजोर हुआ है।

ऐसे में सवाल है कि जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपने हाथ खींच रहे हैं और रुपया अमेरिकी डालर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट दर्ज कर रहा हो, तो आखिर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत कैसे होगा? इसी दबाव के बीच सरकार की ओर से देशवासियों को सोने की चमक से दूर रहने की नसीहत दी जा रही है। वैसे आंकड़ों पर नजर डालें, तो इस वित्त वर्ष में भारत का सोना आयात बिल बढ़कर रिकार्ड 72.4 बिलियन डालर पर पहुंच गया, जो देश के कुल आयात का नौ फीसद से ज्यादा है। सरकार ने व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सोने पर प्रभावी आयात शुल्क छह फीसद से बढ़ाकर पंद्रह फीसद (जीएसटी सहित कुल प्रभावी कर 18.4 फीसद) कर दिया है। जबकि लोगों को सुझाव दिया जा रहा है कि एक साल तक सोना न खरीदें। बढ़ती कीमतों के कारण सोने के आयात में मात्रा के हिसाब से लगभग 70 फीसद तक की गिरावट के बावजूद अंतरराष्ट्रीय बाजार में बनी इमारतें, रास्ते, पुल और रेलवे की पटरियां इस बात की सच्ची गवाही आज भी देते हैं।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ दशकों के दौरान विकास को शासन और प्रशासन संभाल नहीं सके। विकास के नाम पर जिस स्तर का भ्रम चतुर्दिक छाया रहा, उसने विचारों की स्पष्टता को बाधित किया। शासन और प्रशासन का आपसी मान, सम्मान और ताम्बान गलतफहमियों में लिपटा, बिगड़ा और असंतुलित रहा। बीमार, लड़खड़ाते, गिरते पहाड़ों का संताप जांचने और उचित इलाज करने का शुभ मुहूर्त कभी नहीं निकल पाया। विकास से लदी योजनाओं की भरमार से पहाड़ को संभारने और बचाने के लिए ईमानदार प्रयास कभी नहीं हुए। कभी सच की तलहटी में बैठकर यह नहीं सोचा गया कि इन पहाड़ों, नदियों और जंगल को हमारी जरूरत है या हमको इन सबकी। होशियार राजनीति वैसे भी इस तरह के कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। पहाड़ पर विकास की बेलगाम दिशा, पानी, मिट्टी, जंगल और हवा को नुकसान पहुंचा रही है। जिन पहाड़ों ने हमें सब कुछ दिया, हमारा जीवन पाला-पोंसा, हमने उन्हें ही असुरक्षित कर बिसरा दिया है। क्या कभी किसी को विचार करने की जरूरत पड़ी है कि इसका खमियाजा किसे भुगतना पड़ेगा?

अभी तक समझ में यह नहीं आया कि मानवीय शरीर प्रकृति के उन्हीं पांच तत्वों से बना है, जिन्से प्रकृति बनी है। कुदरत की अमानत मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश का जितना खयाल रखेंगे, उतना ही हमारा शरीर बेहतर रहेगा। मानव जीवन प्रकृति पर निर्भर है, लेकिन स्वार्थ के घेरों में कैद ईसान इसे निरंतर नुकसान पहुंचा रहा है। प्रकृति के जीवन को लेकर जिस हद तक उपेक्षा देखी जाती है, वह कई बार परेशान करती है। हिमखंड पिघल रहे हैं, बर्फ नहीं पड़ रही है। यहां तक कि बारिश नहीं होती, लेकिन जब मौसम नाराज होता है, आपदाएं आती हैं, तो स्पष्ट दिखाता है कि ईसान की गुस्ताखियों का परिणाम निकल रहा है। मौसम में इस रफ्तार से बदलाव या उतार-



शायद नीति-निर्माताओं को लगता है कि आम आदमी के घर से बाहर कम निकलने पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के कारोबारियों को सदमा लगेगा और वे कच्चे तेल के दाम कम कर देंगे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारत के व्यापार घाटे

सवाल है कि जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपने हाथ खींच रहे हैं और रुपया अमेरिकी डालर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट दर्ज कर रहा हो, तो आखिर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत कैसे होगा? इसी दबाव के बीच सरकार की ओर से देशवासियों को सोने की चमक से दूर रहने की नसीहत दी जा रही है। वैसे आंकड़ों पर नजर डालें, तो इस वित्त वर्ष में भारत का सोना आयात बिल बढ़कर रिकार्ड 72.4 बिलियन डालर पर पहुंच गया, जो देश के कुल आयात का नौ फीसद से ज्यादा है। सरकार ने व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सोने पर प्रभावी आयात शुल्क छह फीसद से बढ़ाकर पंद्रह फीसद कर दिया है।

का आंकड़ा 333.2 बिलियन डालर तक पहुंच चुका है। ऐसे में सरकार का मानना है कि अगर कोरोनाकाल की तरह ‘घर से काम’ करने की व्यवस्था

जैसे एक फूल बहुत प्यारा और सुंदर है, पर खुशबू नहीं है। ठीक वैसे ही किसी की कही हुई अच्छी बातें व्यर्थ हैं, अगर वह उनको अमल में नहीं लाता।

– महात्मा बुद्ध

को फिर से अपनाया जाए, साझा वाहनों का इस्तेमाल किया जाए या साइकिल से चलने को बढ़ावा दिया जाए, तो पेट्रोल का खर्च बचेगा और देश का विदेशी मुद्रा भंडार संभल जाएगा। मगर, व्यावहारिक तौर पर इसका कितना असर होगा, इसका कोई आकलन अभी तक नहीं किया गया है। भारत अपने कुल आयात का पच्चीस से तीस फीसद हिस्सा केवल कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर खर्च करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के कुल व्यापार घाटे में कच्चे तेल और ईंधन के आयात का शुद्ध योगदान लगभग चालीस से पैंतालीस फीसद के बीच रहा है। वर्ष 2026 के हालिया महीनों में पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनावों और होर्मुज जलमार्ग के बाधित होने से तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। सरकार की ओर से जनता से यह अपील की जा रही है कि भोजन पकाने के तेल की बचत की जाए, ताकि विदेश से आयात होने वाले पाम तेल और अन्य खाद्य तेलों के खर्च को कम किया जा सके। ऐसा लगता है कि अब रसोई में ‘तड़का’लगाने के लिए भी देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार से राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर मामला डालर बचाने का है। जनता अपनी सहेत सुधारें या न सुधारें, मगर सरकार देश के चालू खाता घाटे को सुधारने के लिए रसोई में कड़ाही का तेल तक नापने को तैयार है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से देश में रसायनिक उर्वरकों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। यही वजह है कि सरकार की ओर से किसानों को अब जैविक खेती की सलाह दी जा रही है, जो किसी रासायनिक आपदा के बीच अमृत की तरह परोसी जा रही है। सरकार का मानना है कि जो किसान दशकों से महंगे यूरिया और आयातित कीटनाशकों के सहारे फसल उगा रहे हैं, वे अचानक से जैविक खेती की ओर रुख कर लेंगे, जिससे रसायनिक उर्वरकों के आयात का खर्चा भी कम हो जाएगा। मगर, सवाल यह है कि हकीकत में क्या चंद दिनों के भीतर यह बदलाव संभव हो पाएगा? विदेश यात्राओं और विदेश जाकर शादी समारोह आयोजित करने से फिलहाल परहेज करने का सुझाव भी दिया गया है। इससे आम जनता में डर, घबराहट और संदेह का माहौल पैदा हो रहा है। सरकार के इन सुझावों का सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक ज्यादा रहा है। शेरय बाजार में गिरवट से निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए अब तक बर्बाद हो चुके हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों की जोरदार बिकवाली, व्यवस्थित निवेश योजनाओं से लोगों का पलायन और डालर के मुकाबले शतक छूटा रुपया- इस सबका समाधान क्या आम आदमी की जीवन शैली में निहित है या राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने, गैर तकनीकी सामान के आयात में कमी, गैर जरूरी खर्चों में कटौती, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाकर संभव होगा? आम आदमी का पेट्रोल-डीजल, तेल, सोना और विदेश यात्रा बंद करवा देना लोकातांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल कैसे हो सकता है। सरकार के अर्थशास्त्रियों की अदूरदर्शिता और वैश्विक उथल-पुथल का बोझ जन साधारण के ऊपर डाल देना कतई उचित नहीं है। अब देखना यह है कि ‘त्याग और शुचिता का यह नया माडल’ देश की जीडीपी को कितना ऊपर ले जाता है और जनता कब तक स्वर्ण और तेल के बिना डिजिटल इंडिया का आनंद ले पाती है?

बिटिश हुकूमत निष्ठुर थी, लेकिन अमानवीय नहीं थी। तब महात्मा गांधी की भूख हड़ताल के दौरान उनकी मांगों को मान लिया जाता था। अंग्रेज उनके उपवासों से बनने वाले अंतरराष्ट्रीय दबाव से डरे रहते थे और नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य की निगरानी करते थे। गांधीजी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की चुनौती प्रणाली को जाति के आधार पर विभाजित करने के निर्णय के विरोध में पुणे की यरवदा जेल में अनशन किया था। यह छह दिनों के बाद तब समाप्त हुआ, जब अंग्रेजों ने अपने निर्णय को बदल दिया। मगर लोकतांत्रिक भारत की वर्तमान हुकूमत कहीं अधिक सख्ती दिखा रही है। पिछले कई दिनों तक दिल्ली में सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, मगर सरकार ने उनसे संवाद नहीं किया। बाद में उन्हें जबरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो क्या वांगचुक का गांधीवादी तरीका सही नहीं था? भूख हड़ताल उन पर असर करती है, जो इसके मायने समझते हैं। अन्ना हजारे का उपवास इसलिए सफल होता दिखा था, क्योंकि उस समय की सरकार के कार्यकाल में विरोध-प्रदर्शन की गुंजाइश बनी हुई थी।

– जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

बदलता परिदृश्य

नीट अब केवल मेडिकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षा भर नहीं है। यह देश के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक बदलावों का आईना बन गई है। वर्ष 2026 के परिणामों ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत में उच्च शिक्षा तक पहुंच का दायरा व्यापक हो रहा है। इस वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों की सफलता सबसे अधिक रही है। वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की भागीदारी भी बढ़ रही है। दूसरी ओर छोटे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने सफलता के मामले में बड़े राज्यों को पीछे छोड़ कर यह साबित किया है कि परीक्षा की गुणवत्तापूर्ण तैयारी महत्त्वपूर्ण है। इस वर्ष नीट में सबसे बड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग का रहा। कुल पंजीकरण में इस वर्ग के छात्रों की हिस्सेदारी 41.8 फीसद रही, जबकि सफल छात्रों में यह बढ़ कर 45.7 फीसद पहुंच गई। यह सामाजिक बदलाव का संकेत है।

– कांतिलाल मांडोंत, लखनऊ

मुसीबतों का सफर

‘अनियमितता की पटरी’ (संपादकीय, 15 जुलाई) ने रेल यात्रियों की परेशानियों को स्वर दिया है। यह सही है कि आजकल आरक्षित कोच में भी यात्रा करना बहुत कष्टदायक हो गया है। अनारक्षित टिकट वाले यात्री भी कोच में घुस आते हैं और हर कोच अगले स्टेशन पर उतरने की बात कर बैठ जाता है। इस बीच टोटीई का अठा-पठा नहीं रहता है। कुछ आरक्षित सीटें खाली रहने पर टोटीई बिना टिकट वाले यात्रियों को दे देते हैं। जिनमें कई लोग ऐसे होते हैं, जिनका कोई रिकार्ड रेलवे के पास नहीं होता है। आजकल तो टोटीई आरक्षित सीट पर बैठे यात्रियों के सिर्फ नाम ही पृष्ठते हैं। हो सकता है कि किसी यात्री का पहचान वाला उसका नाम बता कर यात्रा कर ले। बिना पहचानपत्र देखे कैसे मालूम होगा कि सही व्यक्ति यात्रा कर रहा है। इसके अलावा ट्रेनों में चाय तक निम्न स्तर की मिलती है। ऐसे में रेलवे को व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए।

– भगवानदास छारिया, इंदौर

दायित्व का तकाजा

‘जवाबदेही के बरक्स’ (संपादकीय, 21 जुलाई) पढ़ा। यह सच है कि लोकतंत्र की पहचान नागरिकों के प्रति सरकार की जवाबदेही, असहमति एवं शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का सम्मान करने और जनता की आवाज को सुनने से होती है। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर पिछले बीस दिन से दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को जबरन उठा कर अस्पताल ले जाने और संसद मार्च निकाल रहे हजारों युवाओं पर सुरक्षा बलों ने जितने तरह से बल प्रयोग किया, इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं कहा जा सकता। देश की राजधानी में युवाओं की इतनी बड़ी भीड़ का जुटना उनके आत्मबल और लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था का ही प्रमाण कहा जा सकता है।

– कमल कुमार जोशी, अत्मोड़ा



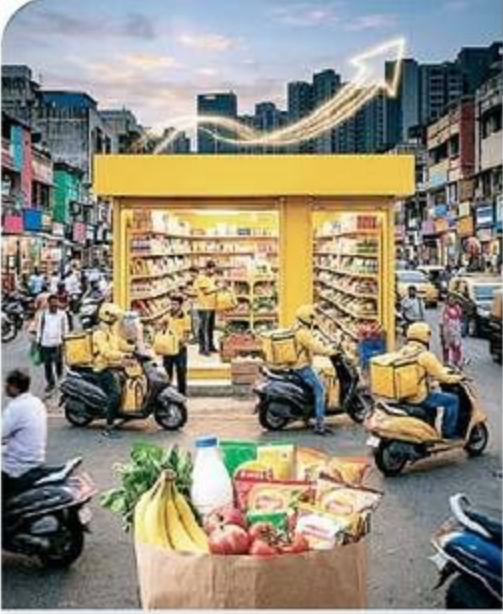
तिमाही नतीजे • ब्लिंकिट और फूड डिलीवरी के दम पर इटर्नल का मुनाफा 268% उछला, रेवेन्यू 182% बढ़ा

ब्लिंकिट: प्रति ग्राहक खर्च 3 साल में 3 गुना बढ़ा

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

भारतीय उपभोक्ता तेजी से अपनी लाइफस्टाइल बदल रहा है। देश की प्रमुख फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी इटर्नल (पूर्व में जोमैटो) का कुल बिजनेस टू कंज्यूमर नेट ऑर्डर वैल्यू एक साल में 54% बढ़कर 31,120 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सबसे बड़ी हिस्सेदारी ब्लिंकिट की रही, जिसका कारोबार 86% बढ़ा। फूड डिलीवरी 20% और 'गोइंग-आउट' बिजनेस 60% बढ़ा। यानी भारतीय ग्राहक का खर्च लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस पर बढ़ रहा है। कंपनी का जून तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 268% बढ़कर 92 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 25 करोड़ रुपए था। हालांकि तिमाही आधार पर मुनाफा 47% घटा है।

कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू 182% बढ़कर 20,211 करोड़ पहुंच गया, जबकि एडजस्टेड एबिटा तीन गुना से ज्यादा बढ़कर 555 करोड़ हो गया। कंपनी के मुताबिक पहले ऑर्डर के बाद चौथी तिमाही में लौटने वाले ग्राहकों का औसत रिटर्शन 46% है। खर्च के लिहाज से यह और दिलचस्प है। जो ग्राहक 3 साल पहले जुड़े थे, वे अब 279% (लाभग 3 गुना) ज्यादा खर्च कर रहे हैं।



ब्लिंकिट के 2443 स्टोर, 200 नए जोड़े

2,443 डार्क स्टोर्स इस तिमाही में ब्लिंकिट ने 200 नए स्टोर्स जोड़े।

1.9 करोड़ वर्ग फीट

कंपनी के कुल वेयरहाउस और डार्क स्टोर्स का क्षेत्रफल।

11 लाख रोजाना

ब्लिंकिट के प्रत्येक स्टोर से प्रतिदिन औसतन 11 लाख की बिक्री हो रही है।

18,288 करोड़

इटर्नल का कुल कैश बैलेंस।

इटर्नल: अप्रैल-जून तिमाही का रिजल्ट (कन्सॉलिडेटेड) एक नजर में

मापदंड	Q1 FY27	Q1 FY26	अंतर
ऑपरेटिंग रेवेन्यू	20,211	7,167	182.0%
टैक्स पूर्व लाभ	272	88	209.1%
ऑपरेटिंग मार्जिन	4.8	6.5	-1.8pp
टैक्स बाद लाभ	92	25	268.0%

(आंकड़े करोड़ रुपए में, pp = परसेंटेज पॉइंट) स्रोत: कंपनी फाइलिंग

टूँड-1 • ऑनलाइन खाना मंगाने की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी

फूड डिलीवरी बिजनेस की ग्रोथ फिर 20% पहुंच गई। यह लगातार चौथी तिमाही है, जिसमें ग्रोथ तेज हुई है। मासिक ट्रांजेक्टिंग ग्राहक बढ़कर 2.72 करोड़ हो गए। इससे संकेत मिलता है कि बाहर खाने और घर पर खाना मंगाने दोनों की मांग साथ-साथ बढ़ रही है।

टूँड-2 • सुविधा कीमत से बड़ी, अब हर माह 33 करोड़ ऑर्डर

जून तिमाही में ब्लिंकिट के मासिक ट्रांजेक्टिंग ग्राहक 3.18 करोड़ तक पहुंच गए, जबकि ऑर्डर 33.1 करोड़ रहे। खास बात यह है कि औसत ऑर्डर वैल्यू 518 रुपए पर लगभग स्थिर रही। इसका मतलब है कि ग्राहक महंगाई के बावजूद सुविधा के लिए नियमित खर्च कर रहा है।

टूँड-3 • अब सिर्फ खाना नहीं, 'आइटिंग' भी एप से प्लान

इटर्नल का 'डिस्ट्रिक्ट' प्लेटफॉर्म 60% की दर से बढ़ा। प्लेटफॉर्म पर 45 हजार रेस्तरां, 5 हजार मूवी स्क्रीन, 7,500 से ज्यादा इवेंट, 6 हजार रियल स्टोर और 2 हजार एक्टिविटी सेंटर जुड़े हैं। यानी अब यह फूड ऐप नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है।

टूँड-4 • ग्राहक बार-बार लौट रहे हैं, ये अब आदत बन चुका

कंपनी ने पहली बार ग्राहक रिटर्शन के आंकड़े भी साझा किए हैं। इसके मुताबिक, नए ग्राहक तीन साल बाद पहले मुकाबले लगभग तीन गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। चौथी तिमाही तक ग्राहक रिटर्शन 46-50% है, जबकि लंबे समय की मांग साथ-साथ बढ़ रहा है।

फूड डिलीवरी लगातार चौथी तिमाही बड़ी सेगमेंट	सालाना बढ़ोतरी
क्विक कॉमर्स	60%
गोइंग-आउट	54%
कुल बी2सी कारोबार	20%

फूड डिलीवरी

रैपिडो, स्विगी से चुनौती... सस्ते खाने के बाजार में उतरेगी इटर्नल

फूड डिलीवरी में ₹50-150 की रेंज वाले सस्ते खाने को लेकर मुकाबला तेज है। रैपिडो (ओनली) और स्विगी (टोइंग) डिस्काउंट के जरिए ग्राहकों को लुभा रहे हैं। हालांकि जोमैटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल का मानना है कि सिर्फ कमीशन और डिलीवरी चार्ज घटाकर यह मॉडल लंबे

समय तक नहीं टिक सकता। टिकाऊ फूड डिलीवरी के लिए डिस्काउंट नहीं, बल्कि सप्लाई चेन में बदलाव जरूरी है। इसी रणनीति के तहत कंपनी बिस्पो विकसित कर रही है। इसमें ऑटोमेशन, सीमित मेन्यू और बड़े पैमाने पर भोजन तैयार कर लागत घटाई जाएगी, जिससे 50-150 में भी मुनाफे के साथ खाना दिया जा सके।

कबाड़ से शाही यॉट: अब अंटार्कटिका और आर्कटिक की बर्फाली वादियों की सैर कराती हैं ये तैरते महल



मिलान | कभी तेल के कुओं तक सामान पहुंचाने वाले ये स्पलाई जहाज आलीशान तैरती हवेलियों में बदल चुके हैं। इटैलियन डिजाइनर स्टेफनो पारस्त्रोचि ने रियायत जहाजों को अंटार्कटिका और आर्कटिक की बर्फाली वादियों की सैर कराने वाले लजरी एक्सप्लोरर यॉट का नया रूप दिया है। इनमें से एक में 116 यात्री और दूसरे में 64 यात्री सफर कर सकते हैं। बाहर से बेहद मजबूत और अंदर 5-स्टार होटल जैसा स्या, वीआईपी सूट और रॉयल लाउंज। कबाड़ से बनाए गए शाही तैरते महल जहाज मालिकों के लिए मुनाफे का सौदा बन गए हैं।

खाद्य तेल संकट बढ़ा...

तिलहन फसलों की बुवाई

सामान्य से 26% कम

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

तिलहन फसलों की बुवाई अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में तिलहन फसलों की बुवाई अभी भी सीजन के सामान्य रकबे से करीब 26% कम है। चालू खरीफ सीजन में तिलहन फसलों का औसत सामान्य रकबा 200.08 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जबकि बुवाई 147 लाख हेक्टेयर ही हुई है। कृषि मामलों के जानकारों का कहना है कि तिलहन फसलों की बुवाई जुलाई तक हो जानी चाहिए, इसके बाद बोई गई फसल में मौसमी प्रकोप और कीड़े लगने का डर रहता है जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्रभावित होता है। इससे भारत की खाद्य तेलों पर आयात निर्भरता और बढ़ सकती है।

सोहिनी दास | मुंबई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा आयातित जेनरिक दवाओं पर 200% तक टैरिफ लगाने की घोषणा से भारतीय फार्मा सेक्टर सहम गया। निफ्टी फार्मा इंडेक्स बुधवार को 1.3% गिरकर बंद हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान लुपिन (-4.2%) के शेयर को हुआ। ऑरिबिंदो फार्मा और डॉ. रेड्डीज के शेयर 2-2% टूटे।

मोतीलाल ओसवाल के तुषार मानधने के मुताबिक, अमेरिका में प्लांट बनाने में 2 साल लगते हैं। उसके बाद एफडीए इंस्पेक्शन और प्रॉडक्ट अप्रूवल में 12-15 महीने और लगते हैं। इसलिए निकट भविष्य में भारतीय सप्लाई पर कोई

ऑरिबिंदो फायदे में; डॉ. रेड्डीज, लुपिन, सिप्ला पर दबाव

1. पांडित्रिक: ऑरिबिंदो फार्मा और सेनेरेस फार्मा को फायदा मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका में पहले से ही उनका मैन्यूफैक्चरिंग ढांचा मौजूद है।

खास असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में इकोसिस्टम बनने में 5 साल लगेंगे। एक्विक्स सिस्कोरिजिज के भारत सेली का मानना है कि 100-200% टैरिफ लगाने से अमेरिका में सस्ती दवाओं की किल्लत और कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। उनके मुताबिक ट्रम्प की

2. नेगेटिव: डॉ.

रेड्डीज, लुपिन, सिप्ला, जयाडस और बायोकाॅन। अमेरिका में इनकी सीमित उपस्थिति है, जिससे ये भारत में बने प्रॉडक्ट्स पर ही ज्यादा निर्भर हैं।

मंशा मोलभाव करने की है। पीएल कैपिटल के परम देसाई का कहना है कि ट्रम्प का 200 जनवरी 2029 तक जारी है, लेकिन कुल दवा खर्च में इनका योगदान सिर्फ 13% है। कम मार्जिन के चलते जेनरिक दवाओं का इकोसिस्टम बनाना घाटे का सौदा है।

सख्ती • बच्चों में बढ़ती लत रोकने के लिए उठाए कदम

सरकार ने दो साल में 50 ओटीटी एप ब्लॉक किए

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

डिजिटल लत को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती मानते हुए केंद्र सरकार ने बीते दो साल में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म ब्लॉक किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट पर बच्चों को आपत्तिजनक कंटेंट, डेटा चोरी और डिजिटल लत से बचाना है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में यह जानकारी दी। यह पूरी कार्रवाई आईटी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और इन्फंडिसेंट रिप्रिजेंटेशन ऑफ वीमेन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1986 के तहत की गई है। अदालत या सरकार का आदेश मिलने के मजह 3 घंटे के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गैर-कानूनी कंटेंट हटाना अनिवार्य कर दिया गया है।

सुरक्षा • बच्चों की ट्रैकिंग और विज्ञापनों पर रोक

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत बच्चों का पर्सनल डेटा इस्तेमाल करने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य है। बच्चों की ऑनलाइन ट्रैकिंग, व्यावहारिक निगरानी और लक्षित विज्ञापनों पर रोक है। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट का उद्देश्य भी युवाओं को वित्तीय नुकसान से बचाना है।

मंत्रालय ने इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का हवाला देते हुए कहा है कि 15-29 साल के युवाओं में डिजिटल लत एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभरी है। इससे युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य और कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है।

बिजनेस बीफ

मैंगो पेय में 22-25% पल्प की सिफारिश

नई दिल्ली। सरकारी समिति ने आम आधारित पेय पदार्थों में 22-25% प्राकृतिक मैंगो पल्प अनिवार्य करने की सिफारिश की है। इस मानक को पूरा करने वाले उत्पादों को ही 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य तोतापुरी आम की मांग और कीमतें बढ़ाकर किसानों को राहत देना है।

दो महीने के निचले स्तर के करीब पहुंचा रुपया

मुंबई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को रुपया 28 पैसे कमजोर हुआ। वजह पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों का छह हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचना। स्थानीय मुद्रा मंगलवार के 96.25 प्रति डॉलर के बंद भाव के मुकाबले 96.53 प्रति डॉलर पर बंद हुई।

जंग के चलते एचपीसीएल, बीपीसीएल को भारी घाटा

मुंबई। एचपीसीएल को जून तिमाही में 11,526 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। जबकि बीपीसीएल को तिमाही में 3,962 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इन तेल कंपनियों के मुताबिक ईران जंग के चलते कच्चे तेल के दाम 50% तक बढ़े। इसके बावजूद लागत से कम कीमत पर ईंधन बेचने से मुनाफा खत्म हो गया।

सेबी ने 34 एडवाइजर्स के लाइसेंस रद्द किए

मुंबई। बाजार नियामक सेबी ने नवीनीकरण शुल्क न चुकाने पर 34 इन्वेस्टमेंट एडवाइजरों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए। नियमों के तहत हर पांच साल में फीस देना अनिवार्य है। फीस न भरने के कारण 11 रिसर्च एनालिस्ट्स के रजिस्ट्रेशन भी रद्द किए गए। ये संस्थाएं पुराने कामकाज व निवेशकों की शिकायतों के लिए जवाबदेह बनी रहेंगी।

बिजनेस एंकर

रियल एस्टेट का नया स्टेटस सिंबल लैंडमैकिंग, 146% बढ़ी प्राइवेट आइलैंड, महलों की मांग

अब सिर्फ लजरी घर नहीं, पूरा इलाका खरीद रहे अरबपति

बिजनेस संवाददाता | न्यूयॉर्क

इंटरनेट की दुनिया में शारीरिक बनावट और सुंदरता को निखारने के लिए लुक्समैकेकिंग का चलन काफी लोकप्रिय है, लेकिन अरबपतियों और अमीर तबके की दुनिया में अब 'लैंडमैकिंग' का नया दौर शुरू हो चुका है। लैंडमैकिंग यानी अधिकतम निजता, प्राकृतिक दृश्य और भविष्य की सुरक्षा के लिए अपने घर के आसपास की जमीन और पड़ोसी संपत्तियों को महंगे दामों में खरीदकर विशाल साम्राज्य बनाना।

कालवेल बैंकर ग्लोबल लजरी की रिपोर्ट के अनुसार, जमीन की खोज में सालाना आधार पर 97% की भारी वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, निजी द्वीपों, ऐतिहासिक महलों और



बड़ी संपत्तियों के लिए पूछताछ 146% तक बढ़ गई। दुनिया के शीर्ष अरबपति इस रणनीति को तेजी से अपना रहे हैं। अमेजन के शीर्ष अरबपति जेफ बेजोस ने मियामी के इंडियन क्रीक आइलैंड पर तीन संपत्तियां खरीदने के लिए लगभग 234 मिलियन डॉलर (2,259 करोड़ रुपए) खर्च कर दिए हैं। वहीं,

सिटाडेल के संस्थापक केन ग्रिफिन पाम बीच में 25 एकड़ जमीन को जोड़कर दुनिया के सबसे महंगे निजी आवासों में से एक बना रहे हैं। हाल ही में एक और उदाहरण देखने को मिला जब अरबपति लैरी एलिसन और डेविड मैकनिल ने मिलकर मानालापम में 67 मिलियन डॉलर (647 करोड़ रुपए) की एक

चार एकड़ जमीन को आधा-आधा आपस में बांट लिया, ताकि वहां कोई तीसरा व्यक्ति नया आलीशान घर न बना सके और उनकी गोपनीयता बनी रहे। अमीरों का यह ट्रेंड साउथ फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि यहां अमीर खरीदारों की संख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन प्राइम

लोकेशन पर जमीन सीमित है। इस सीमित आपूर्ति के कारण खरीदार पड़ोसियों को बाजार मूल्य से 20% तक अधिक प्रीमियम देने को तैयार हैं। अस्ट्रा-रिच खरीदारों में 63% से अधिक सौदे ऑल-कैश (नकद) हो रहे हैं, ताकि प्रक्रिया तेज रहे और संपत्ति खुले बाजार में जाने से पहले ही उनके हाथ लग जाए।

डॉ. रेड्डीज का मुनाफा 69% और कमाई 6% घट गई

भास्कर न्यूज़ | हैदराबाद

फार्मा दिग्गज डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जून तिमाही में सालाना आधार पर 69% घटकर 443 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 1,418 करोड़ रुपए था। लिनालिडोमाइड रेवेन्यू में सुस्ती और सेमाग्लुटाइड एपीआई से जुड़े 240 करोड़ रुपए के एकमुश्त प्रावधान के कारण बड़ा असर पड़ा है। कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी 6% घटकर 8,071 करोड़ रुपए रहा, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 8,545 करोड़ रुपए था। वहीं एबिटा 56% गिरकर 1,009 करोड़ रुपए पर आ गया। मार्जिन सिक्वडिजिट 12.5% बचा। माल दुलाई और सॉल्वेंट की लागत बढ़ने से भी कंपनी का मार्जिन प्रभावित हुआ। इस तिमाही के अंत में कंपनी के पास 3,058 करोड़ का नेट कैश संपत्तस रहा।

टूँड • भारतीयों ने मई में विदेश भेजे 23,071 करोड़

विदेश यात्रा-पढ़ाई पर खर्च 7.7% घटा, शेरयों में निवेश दोगुना बढ़ा

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

मई 2026 में विदेश यात्रा और पढ़ाई पर खर्च घटा है, जबकि शेयरों और डेट में भारतीयों का निवेश दोगुना बढ़ा है। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत भारतीयों द्वारा विदेश भेजा गया कुल पैसा सालाना 3.6% बढ़कर 2.39 अरब डॉलर (करीब 23,071 करोड़ रुपए) पहुंच गया। इसमें मुख्य योगदान बैंक डिपॉजिट का रहा, जो दोगुना होकर 11.81 करोड़ डॉलर हो गया। इसी तरह, इक्विटी और डेट में निवेश भी दोगुना बढ़कर 3,510 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। हालांकि प्रॉपर्टी खरीदारी पर खर्च 14.22% घटकर 3.58 करोड़ डॉलर रह गया।

अप्रैल-मई में एनआरआई जमा 29% घट गया

अप्रैल-मई के दौरान एनआरआई द्वारा स्वदेश भेजा गया पैसा 29.25% घटकर करीब 12,838 करोड़ रुपए रह गया। आरबीआई के मुताबिक एनआरआई और एफसीएनआर (बी) खातों में कम पैसा आने से यह गिरावट आई। इस दौरान एफसीएनआर खातों में 28.2 करोड़ और एनआरआई में 59.7 करोड़ डॉलर आए।

विदेश भेजने वाले कुल पैसे में सबसे बड़ा हिस्सा यात्रा खर्च का रहा, जो 7.7% घटकर 1.28 अरब डॉलर दर्ज हुआ। पढ़ाई का खर्च 38% घटकर 9.26 करोड़ डॉलर रह गया।

Lifetime Free Newspapers Access

Editorials PDF

- English Editorials PDF with International Newspapers Editorials [35-40 pages]
- Hindi Editorials PDF
- Daily Vocabulary PDF

Magazine Channel

National & International
[General & Exam related]

International Newspapers

Newspapers around world.
Asian, European & American

Hindi Newspapers

- 1) दैनिक जागरण
- 2) जनसत्ता
- 3) हरिभूमि
- 4) हिंदुस्तान

Indian Newspapers Channel

1. The Indian Express

2. The Hindu

3. Business Line

4. Financial Express

5. Times of India

6. Hindustan Times

7. Economic Times

8. Live Mint

9. Business Standard

Click below to Join
this Community 

